

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA)

National University of Education
Planning and Administration
(NUEPA)

शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा स्थापित भारत ही नहीं दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है।

जो शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में इसके द्वारा किया जा रहा है जिसकी देखरेख द्वारा भारत सरकार ने अगस्त 2006 में इसका उन्नयन करके मानद विश्व विद्यालय का दर्जा प्रदान किया ताकि यह स्वयं उपाधि प्रदान कर सके। अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के समान न्यूपा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है।

स्थापना - 1962

स्थान - नई दिल्ली

सम्बद्धताएं - U.C.C

आरम्भ में न्यूपा की स्थापना 1962 में एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र के शैक्षिक क्षेत्र के शैक्षिक

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

- RMSA -

माध्यमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का गठन किया गया।

इसके मार्च 2009 में शुरू किया गया था। सभी के लिए एक कुशल विकास और रणनीति के लिए शर्त प्रदान करने के लिए योजना का कार्यान्वयन 2009-2010 से शुरू हुआ है। इस योजना में एक बहु-धारायामी अनुसंधान-तकनीकी परामर्श, विभिन्न कार्यान्वयन और धन सहायता शामिल है।

मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और कुल नामांकन दर को 52% (2005-2006) के अनुसार पांच वर्षों में 75% तक बढ़ाना है। अर्थात् 2009-2014 से इसका उद्देश्य 15-16 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, केन्द्रीय मन्त्रालय से धन राज्य सरकारों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। जो अलग अलग

कार्यान्वयन एजेंसियों की
स्थापना करते हैं।

Date
24/11/20

माध्यमिक शिक्षा के लिए योजना
शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति →

NPE

के बाद से 1986 की शुरुआत
अवधि के तहत माध्यमिक
और उच्च माध्यमिक विद्यालय
प्रणालियों की संरचना और
संगठन में कोई बड़ा

बदलाव नहीं हुआ।
⇒ इस योजना में ध्यान देने के

विभिन्न असमानताओं को
कम करने पर था

पाठ्यक्रम को महत्व देने को
नवीनीकृत करने पर था।

व्यवसायीकरण और रोजगार
उन्मुख पाठ्यक्रमों।

यह खुली शिक्षा प्रणाली, शिक्षक
प्रशिक्षण और I.C.T. के विस्तार

और विविधता का महत्व
दता है। लड़कियों के लिए मुक्त

शिक्षा व दूरवास की व्यवस्था
और विकलांग बच्चों के लिए

संकीर्ण शिक्षा भी उजागर किया
गया है।

निजी क्षेत्रों की भागीदारी

और सरकारी

संगठनों (N.G.O) सहित निजी क्षेत्र की बड़ी हुई भागीदारी थी। वर्तमान में ये निजी क्षेत्र लगभग 51%।

माध्यमिक स्कूलों और 58% उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का प्रबंधन करते हैं।

- इन सच्यों के लिए व्यवस्थित पुंदाजी किये जाय जो सम्पर्क केंद्रों और मल्टी मीडिया चैनलों का उपयोग करके राष्ट्रीय व राज्यभूक्त स्कूलों के माध्यम से द्वैपचारिक शिक्षा प्रणालियों में खुद को नामांकित नामांकित करने में सक्षम नहीं थे।

- इसने केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता के साथ विशेष रूप से पर्यावरण शिक्षा विज्ञान गणित और कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्रों और शिक्षा की गुणवत्ता पर अल्पधिक सुधार पर जोर दिया।

संशोधित NPE नीति 1992 के बाद पाठ्यक्रम में संशोधन मूल्य शिक्षा के लिए संघान केंद्रों व कम्प्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र आदि जैसे नई पहल की गयी।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा

विकलांगता अधिनियम, 1995 के साथ व्यक्तियों के अधिनियम के साथ CWISN के लिए शिक्षाने ने प्रेरणा प्राप्त की यह अधिनियम कुछ सरकारों और अधिकारियों को शिक्षा के प्रति इन बच्चों के लिए मुक्त पंहुच के प्रावधान के लिए कुछ उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटित परिवहन में गैर भेदभाव उनके लिए अनुसन्धान के वितीय पालसान आदि प्रदान करता है।

इस योजना ने इन बच्चों की खातिर शिक्षा के बीच व्यवहार में परिवर्तन व क्षमता निर्माण के कार्यक्रम भी शुरू किये।

~~योजनाकारों के प्रशासकों और~~
~~पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के निश्च~~
~~रणीया क्षेत्र के यूनेस्को केन्द्र के~~
~~रूप में की गई थी। जिसे~~
 1965 में एशिया शैक्षिक योजना
 एवं प्रशासन संस्थान बना दिया
 गया इसके 4 वर्ष बाद भारत सरकार
 ने इसका अद्यग्रहण कर लिया
 और इसका नाम "राष्ट्रीय शैक्षिक
 योजना एवं प्रशासन कालेज
 की बढ़ती भूमिकाओं और
 कार्य कलापो, विशेषकर क्षमता
 विकास शोध और सरकारों को
 दी जा रही व्यवसायिक समर्थन
 कारी सेवाओं को ध्यान में
 रखते हुए 1979 में पुनः इसका
 नाम बदलकर "राष्ट्रीय शैक्षिक
 योजना एवं प्रशासन संस्थान
 बना कर दिया गया।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन
~~संस्थान~~ विश्वविद्यालय (न्यूपा) में
 10 विभाग हैं। इसमें प्रतिष्ठित
 बहुशास्त्रीय संकाय है विश्वविद्यालय
 का पुस्तकालय बहुत समृद्ध है।
 इसमें शैक्षिक योजना एवं प्रशासन
 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पुस्तकें
 राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल
 और सरकारी दस्तावेज उपलब्ध हैं।

विश्वविद्यालय अपने बहुआयामी
गतिविधियों के अलावा शिक्षा नीति
योजना और प्रशासन के क्षेत्र में
अन्तर शास्त्रीय समाज विज्ञान के
परिप्रेक्ष्य में एमफिल, पीएचडी
और अंश काथलिक पीएचडी
पाठ्यक्रम भी संचालित करता है।
न्यूपा के शोध कार्यक्रम में
राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण
से शिक्षा के सभी स्तरों और
प्रकारों को शामिल किया जाता है।